दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-८९ वा | मंगळवार २० जनवरी २०२६ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का भारत दौरा: मात्र ढाई घंटे की 'पॉवर विजिट' के बड़े मायने

नई दिल्ली, १९ जनवरी
तामीर न्यूज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष निमंत्रण पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (MBZ) आज भारत पहुंचे। यह दौरा अपनी संक्षिप्त अवधि के कारण खासा चर्चित रहा, जो मात्र ढाई से तीन घंटे का था। पीएम मोदी ने खुद दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाया और एक ही कार में सवार होकर आगे बढ़े। यह चइन की राष्ट्रपति पद संभालने के बाद भारत की तीसरी आधिकारिक यात्रा है और पिछले दशक में पांचवीं। यह दौरा पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव (ईरान-अमेरिका संबंधों में खटास, गाजा अस्थिरता) के बीच हुआ, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'Board of Peace for Gaza' प्रस्ताव के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दौरा क्यों इतना संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण? इस 'वर्किंग विजिट' या 'पॉवर मीटिंग' के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

ट्रंप के 'Board of Peace' पर समन्वय

ट्रंप ने गाजा में स्थायी शांति के लिए 'Board of Peace' का प्रस्ताव दिया है, जिसमें भारत को भी निमंत्रण मिला है। यूएई इस बोर्ड का महत्वपूर्ण सदस्य है। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता, गाजा शांति रोडमैप और वैश्विक सहयोग पर विस्तृत चर्चा की। यह दौरा ट्रंप योजना के क्रियान्वयन में भारत-यूएई समन्वय को मजबूत करने का संकेत देता है।

ऊर्जा, निवेश और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस

यूएई भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में बड़ा भागीदार है। बैठक में भविष्य के निवेश, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और ऊर्जा सुरक्षा पर मुहर लगी।

व्यापक रणनीतिक साझेदारी की मजबूती

दोनों देश अब 'Comprehensive Strategic Partners' हैं। झच् मोदी और चइन के बीच व्यक्तिगत 'कैमिस्ट्री' ने संबंधों को नई ऊंचाई दी है।

भारत-यूएई संबंध: आंकड़ों में मजबूती

द्विपक्षीय व्यापार: वर्तमान में ८५-१०० बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है (FY २०२४-२५ में णड १००.०६ बिलियन तक पहुंचा)। उएझ- के बाद अभूतपूर्व उछाल आया, लक्ष्य जल्द १०० बिलियन डॉलर से अधिक करना है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

निवेश: यूएई भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। सॉवरेन वेल्थ फंड्स बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों और डिजिटल ▶▶पान ४ पे

समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश

सांसद बजरंग सोनवणे का अधिकारियों को आदेश; अंबाजोगाई मेडिकल कॉलेज में आगंतुक समिति की विस्तृत बैठक

अंबाजोगाई: स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई में आज आगंतुक समिति की बैठक सांसद बजरंग सोनवणे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने मराठवाड़ा के ग्रामीण और आम मरीजों को समय पर, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दिए। इस उद्देश्य से अस्पताल के विभिन्न विभागों के कामकाज की गहन समीक्षा की गई।

बैठक में डीन डॉ. शंकर धपाटे, समिति सदस्य पूर्व विधायक संजय दौंड, राजकिशोर पापा मोदी, वसंत मुंडे, संजीवनी देशमुख, साथ ही डॉ. नरेंद्र काले, अमर देशमुख सहित अस्पताल के विभिन्न विभागों के प्रमुख और अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान CT Scan के बाद रेडियोलॉजिस्ट से समय पर रिपोर्ट न मिलने से मरीजों और उनके परिजनों को होने वाली परेशानियों पर चर्चा हुई। रेडियोलॉजिस्ट के स्वीकृत पदों, वास्तविक कार्यरत संख्या, उनकी उपस्थिति और कार्य-घंटों को लेकर स्पष्टता लाने के निर्देश दिए गए। चठख मशीन चालू होने के बावजूद लंबी प्रतीक्षा सूची की समस्या पर अपॉइंटमेंट प्रक्रिया में सुधार के आदेश दिए गए।

सुपर स्पेशियलिटी विभाग में डॉक्टरों के स्वीकृत और कार्यरत पदों की स्थिति, उपलब्ध विशेषज्ञों के प्रभावी उपयोग तथा कुछ सेवाओं के अपेक्षित क्षमता से कम संचालन पर भी चर्चा हुई। २ऊ एलहे जांच के लिए मरीजों को निजी अस्पतालों में न भेजना पड़े, इसके लिए आवश्यक मानवबल और उपकरण उपलब्ध कराने ▶▶पान ४ पे

२९ महानगरपालिकाओं के महापौर पद के आरक्षण को आखिरकार मिला 'मुहूर्त'

नगर विकास विभाग २२ जनवरी को निकालेगा आरक्षण की लॉटरी

जमीर काज़ी
मुंबई (प्रतिनिधि):

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सहित राज्य की २९ महानगरपालिकाओं में महापौर चयन की प्रक्रिया अब पटरी पर आ गई है। नगर विकास विभाग की ओर से २२ जनवरी को सुबह ११ बजे मंत्रालय की छठी मंज़िल स्थित सभागृह में महापौर पद के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद २९ महानगरपालिकाओं में इस पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

तीन दशक बाद ठाकरे गुट को सत्ता से बाहर करने वाली मुंबई महानगरपालिका में महापौर पद किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा, इस पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं। हाल ही में राज्य की २९ महानगरपालिकाओं के चुनाव संपन्न हुए, जिनके नतीजे १६ जनवरी को घोषित किए गए थे। हालांकि, महापौर पद का आरक्षण अब तक घोषित न होने से राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बनी हुई थी।

किस महानगरपालिका में महापौर पद सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा, इसी पर आगे की राजनीतिक समीकरण तय होंगे। इसी कारण इस आरक्षण लॉटरी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। आखिरकार राज्य सरकार ने इस सस्पेंस को खत्म करते हुए महापौर पद के आरक्षण की लॉटरी का आधिकारिक कार्यक्रम घोषित किया है।

नगर विकास विभाग की जानकारी के अनुसार, गुरुवार २२ जनवरी को राज्य की सभी २९ महानगरपालिकाओं के महापौर पद के लिए आरक्षण तय करने की लॉटरी निकाली जाएगी। इससे मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ सहित अन्य प्रमुख शहरों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि महापौर किस वर्ग से होगा।

इस बार महानगरपालिका चुनावों में महायुति और भाजपा ने कई स्थानों पर बढ़त हासिल की है। मुंबई, ठाणे, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ जैसे बड़े शहरों में सत्ता के समीकरण बदले हैं। कुछ महानगरपालिकाओं में कांग्रेस और सहयोगी दलों ने भी सत्ता बनाई है, जबकि विरार में बहुजन विकास आघाड़ी को जीत मिली है। बावजूद इसके, चुनाव परिणाम आने के बाद भी महापौर कौन होगा, यह सवाल अनुत्तरित था। अब आरक्षण लॉटरी के बाद इस प्रक्रिया को गति मिलेगी।

शासन द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, यह लॉटरी माननीय राज्यमंत्री (नगर विकास) की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। मंत्रालय, मुंबई की छठी मंज़िल स्थित परिषद सभागृह में ▶▶पान ४ पे

राज्य के किसानों के कर्ज का होगा पुनर्गठन

१७ लाख किसानों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय

नई दिल्ली, (संवाददाता):

महाराष्ट्र के १७.२९ लाख किसानों के २६,६५८.७७ करोड़ रुपये के बकाया कर्ज के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने खातों को चिन्हित कर लिया है। इस संबंध में सदस्य बैंकों ने पहले ही महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) को जानकारी दे दी है।

संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत, पुनर्गठित कर्ज की राशि पर पहले वर्ष के लिए रियायती ब्याज दर उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरे वर्ष से इस कर्ज पर सामान्य ब्याज दर लागू होगी, यह भी स्पष्ट किया गया है।

महाराष्ट्र के कई जिलों में अत्यधिक वर्षा और बेमौसम बारिश के कारण भारी फसल नुकसान हुआ है, जिससे किसान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इस मुद्दे को कई सांसदों द्वारा केंद्र सरकार के संज्ञान में लाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित किसानों पर कर्ज चुकाने के लिए बैंकों द्वारा कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। प्रभावित किसानों से कर्ज वसूली अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है, ताकि उनका मानसिक और आर्थिक बोझ कम किया जा सके।

मुख्य बिंदु:

पहला वर्ष: पुनर्गठित कर्ज पर ब्याज में छूट मिलेगी।

दूसरा वर्ष: सामान्य ब्याज दर लागू होगी।

कर्ज वसूली के लिए बैंकों का कोई दबाव नहीं।

महाराष्ट्र एसएलबीसी की रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी दी गई है। एसएलबीसी के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने २६ नवंबर २०२५ के पत्र के माध्यम से राज्य में प्राकृतिक आपदा घोषित की है। इसके बाद एसएलबीसी ने राज्य की सभी सदस्य बैंकों ▶▶पान ४ पे

बिना हेलमेट कार्यालय आने वाले कर्मचारियों पर हजार रुपये का जुर्माना

बीड (प्रतिनिधि): केंद्र सरकार का सड़क सुरक्षा अभियान-२०२६ शुरू होने के बाद बीड जिला सड़क सुरक्षा समिति ने सबसे पहले शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों से हेलमेट पहनने की अपील की थी। इसके बावजूद कई कर्मचारी दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे थे।

इस पर आज जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तहसील, न्यायालय, पंचायत समिति, नगरपालिका, जिला परिषद सहित अन्य सभी शासकीय-प्रशासकीय कार्यालयों के प्रवेश द्वारों पर कड़ा पहरा लगाया।

बिना हेलमेट कार्यालय परिसर में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों पर यातायात पुलिस ने दंडात्मक कार्रवाई की। दोपहर एक बजे तक सौ से अधिक कर्मचारियों पर कार्रवाई होने की जानकारी पुलिस ने दी। नियम उल्लंघन पर प्रत्येक कर्मचारी से एक हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया, जिससे बिना हेलमेट आने वालों को बड़ा झटका लगा।

वहीं दूसरी ओर, हेलमेट पहनकर आने वाले कर्मचारियों का यातायात पुलिस ने गुलाब का फूल देकर स्वागत किया।

जिले में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए हेलमेट अनिवार्य किया गया है। इसी संदर्भ में जिला पुलिस अधीक्षक नवनीत कांवत ने शासकीय कर्मचारियों के लिए हेलमेट उपयोग के सख्त निर्देश जारी किए थे और इसका परिपत्र सभी कार्यालयों को भेजा गया था। आज से इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन की शुरुआत की गई।

सुबह से ही यातायात शाखा के पुलिसकर्मी कलेक्टर कार्यालय, जिला परिषद, नगरपालिका, तहसील सहित अन्य कार्यालयों के बाहर तैनात रहे। बिना हेलमेट आने वाले कर्मचारियों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। आज कुल मिलाकर सौ से अधिक कर्मचारियों पर यह कार्रवाई की गई।

अंबरनाथ नगर परिषद में शिंदे-राष्ट्रवादी गठबंधन की सत्ता पर हाईकोर्ट की रोक

भाजपा की शिंदे गुट के खिलाफ याचिका स्वीकार

जमीर काज़ी । मुंबई

चुनाव नतीजों के बाद नगरसेवकों की तोड़फोड़ और जोड़तोड़ के कारण चर्चा में आई अंबरनाथ नगर परिषद में सत्ता गठन का विवाद अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। एक सप्ताह पहले शिंदे गुट की शिवसेना द्वारा गठित समिति के चयन पर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्थगनादेश दिया है। भाजपा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ठाणे के जिलाधिकारी को इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

इस आदेश के बाद अब यह तय करना जिलाधिकारी के समक्ष होगा कि शिंदे गुट की शिवसेना ने अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई गई शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस की आघाड़ी वैध है या फिर भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस के नगरसेवकों के समर्थन से बनाई गई नई आघाड़ी सही मानी जाए।

शिंदे-अजित पवार गुट द्वारा गठित सत्तारूढ़ विकास आघाड़ी के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति अभय मंत्री की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। अदालत ने आघाड़ी के अंतिम निर्णय तक नगर परिषद की विभिन्न समितियों के गठन पर लगी रोक बरकरार रखते हुए, दोनों आघाड़ियों की सहमति से यह मामला निर्णय के लिए जिलाधिकारी को भेजने का निर्देश दिया। साथ ही, जिलाधिकारी को कानूनी प्रावधानों के अनुसार फैसला लेने को कहा गया और याचिका का निपटारा किया गया।

अदालत के आदेश के अनुसार, दोनों आघाड़ियों को २८ जनवरी तक जिलाधिकारी कार्यालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद जिलाधिकारी को दोनों पक्षों को सुनकर अनावश्यक स्थगन के बिना अगले २१ दिनों के भीतर निर्णय देना होगा। साथ ही, निर्णय चाहे जो भी हो, उस पर १५ दिनों की स्थगन अवधि रहेगी, ताकि यदि कोई पक्ष चुनौती देना चाहे तो उसे अवसर मिल सके। इस प्रकार, मार्च २०२६ तक अंबरनाथ नगर परिषद की समितियों के गठन की प्रक्रिया नहीं हो सकेगी। इसी कारण समितियों के गठन के लिए आज प्रस्तावित महासभा भी अदालत के आदेश के चलते रद्द कर दी गई।

क्या है पूरा मामला?

अंबरनाथ नगर परिषद की सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा ने १२ नगरसेवकों वाली कांग्रेस के साथ-साथ अजित पवार गुट के चार नगरसेवकों और एक अपक्ष को साथ लिया। इसके चलते प्रदेश कांग्रेस ने ११ नगरसेवकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अगले ही दिन इन सभी ने भाजपा में प्रवेश किया। वहीं, शिंदे गुट ने अजित पवार ▶▶पान ४ पे

ओबीसी बहुजन पार्टी और कांग्रेस की ज़िला परिषद-पंचायत समिति चुनाव के लिए महाआघाड़ी

धनगर, ओबीसी, मराठा सहित सभी समाजों को धोखा देकर फडणवीस ने राज्य में जातीय संघर्ष भड़काया-प्रकाश शेंडगे

जमीर काज़ी

मुंबई : राज्य में ओबीसी बहुजन पार्टी और कांग्रेस के बीच आघाड़ी बन गई है और आगामी ज़िला परिषद तथा पंचायत समिति के चुनाव दोनों दल मिलकर लड़ेंगे। यह घोषणा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने सोमवार को आयोजित एक पत्रकार परिषद में की।

ओबीसी बहुजन पार्टी के नेता प्रकाश अण्णा शेंडगे ने अपने सहयोगियों चंद्रकांत बावकर, जे. टी. तांडेल और पांडुरंग मिरगळ के साथ टिळक भवन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से विस्तृत चर्चा की। इसके बाद हुई संयुक्त पत्रकार परिषद में हर्षवर्धन सपकाळ ने आघाड़ी की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने

कहा कि यह आघाड़ी केवल चुनाव के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए बनाई गई है।

सपकाळ ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा जाति-आधारित जनगणना की लगातार मांग के बाद मोदी सरकार को इस विषय पर निर्णय लेना पड़ा, लेकिन अब तक जातिगत जनगणना पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस की स्पष्ट नीति है-जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस रुख को सभी समाजों का समर्थन मिल रहा है और धनगर व ओबीसी समाज के उचित प्रतिनिधित्व पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि २०१४ में बारामती में देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता में आते ही धनगर समाज को आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन आज तक उसे पूरा नहीं किया गया। फडणवीस ने धनगर, ओबीसी, मराठा और आदिवासी समाज को आरक्षण के नाम पर ठगा है और समाजों के बीच टकराव पैदा किया है। अब इन समाजों का भाजपा और फडणवीस पर से भरोसा उठ चुका है।

इस अवसर पर प्रकाश शेंडगे ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है और २७ प्रतिशत आरक्षण पर भी हमला हो रहा है। एक के बाद एक जीआर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी समाज को वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा। ओबीसी समाज को न्याय दिलाने के लिए स्वतंत्र पार्टी बनाकर समान विचारधारा वाले दलों के साथ आघाड़ी करने का निर्णय लिया गया है। जाति-आधारित जनगणना का समर्थन करने के लिए उन्होंने राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में ही ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझेगा। भिवंडी के नवनिर्वाचित नगरसेवकों का सम्मान भिवंडी महानगरपालिका चुनाव में विजयी कांग्रेस के ३० नगरसेवकों का सम्मान प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ के हाथों किया गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व विधायक वजाहत मिर्झा, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष (संगठन व प्रशासन) एडवोकेट गणेश पाटील, भिवंडी ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व विधायक रशीद ताहिर मोमिन, प्रभारी राजेश शर्मा, प्रदेश महासचिव नूर अंसारी, जावेद फारुखी, रमाकांत भोई सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित

देश में सबसे पहले रोज़ा इफ्तार का आयोजन करने वाली अहिल्यामाई होळकर की प्रतिमा से छेड़छाड़, समता पर हमला

पुना प्रतिनिधि :

भारत के सामाजिक समता के इतिहास में राजमाता, राष्ट्रमाता अहिल्यामाई होळकर का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। देश में सबसे पहले मुस्लिम समाज के लिए रोज़ा इफ्तार का आयोजन कर धार्मिक सौहार्द और समानता का संदेश देने वाली अहिल्यामाई होळकर को सामाजिक न्याय, सर्वधर्म समभाव और मानवता की प्रतीक माना जाता है।

ऐसी महान और समावेशी विचारधारा की प्रतीक अहिल्यामाई होळकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ की घटना को केवल एक मूर्ति का अपमान नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह भारतीय संविधान में निहित समता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल मूल्यों पर सीधा हमला है।

जानकारी के अनुसार, हाल के वर्षों में देश में हिंदू-मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा देने वाली राजनीति तेज़ हुई है। चुनावी स्वार्थ के लिए समाज को धार्मिक रेखाओं में बांटने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आपसी विश्वास और सौहार्द को नुकसान पहुँच रहा है। ऐसे वातावरण में समता और भाईचारे का संदेश देने वाली ऐतिहासिक विभूति की प्रतिमा को निशाना बनाया जाना गंभीर चिंता का विषय है।

उठते सवाल

प्रतिमा से छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? सरकार इस घटना पर स्पष्ट और कड़ा रुख क्यों नहीं अपना रही?

समतावादी और धर्मनिरपेक्ष इतिहास को मिटाने के पीछे किसका एजेंडा है?

सकारात्मक पक्ष और समाज की अपेक्षा

अहिल्यामाई होळकर की विरासत सर्वधर्म समभाव और सामाजिक एकता को मजबूत करती है। उनका शासनकाल न्यायप्रिय, लोककल्याणकारी और समावेशी रहा है। ऐसी घटनाओं पर त्वरित न्याय से समाज में शांति और विश्वास कायम रहेगा।

सभी समुदायों को मिलकर संविधानिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए।

मुस्लिम समाज की भूमिका

मुस्लिम समाज ने सदैव देश की एकता, संविधान और सामाजिक सौहार्द का समर्थन किया है। रोज़ा इफ्तार जैसे आयोजनों के माध्यम से समता का संदेश देने वाली अहिल्यामाई होळकर जैसी न्यायप्रिय शासक पर मुस्लिम समाज को गर्व है। समाज की ओर से मांग की गई है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और सामाजिक समरसता को ठेस पहुँचाने वाली ताकतों को रोका जाए।

क़ाज़ी तक़ीउद्दीन ज़हीरुद्दीनने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी हासिल की

मुंबई, १९ जनवरी , संवाददाता

खारघर, मुंबई स्थित सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. क़ाज़ी तक़ीउद्दीन ज़हीरुद्दीन (मूल निवासी नांदेड़, वर्तमान में मुंबई) ने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री सफलतापूर्वक पूर्ण की है। उनके शोध प्रबंध का विषय A Multi Criteria Decision Making -pproach for Sustainability Assessment of Thermal Power Plants रहा, जिसमें थर्मल पावर प्लांट्स की सततता (सस्टेनेबिलिटी) के आकलन हेतु मल्टी-क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग पद्धति पर आधारित शोध प्रस्तुत किया गया है।

डॉ. क़ाज़ी तक़ीउद्दीन ने स्नातक डिग्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद से प्राप्त की, जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री एसआरटीएम विश्वविद्यालय, नांदेड़ से पूरी की। उन्हें शिक्षण क्षेत्र में २५ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के मान्यता प्राप्त पोस्टग्रेजुएट गाइड हैं और अब तक उनकी देखरेख में २२ स्नातकोत्तर छात्र डिग्री प्राप्त कर चुके हैं।

उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स और सम्मेलनों में शोध पत्र प्रकाशित किए हैं तथा अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय तकनीकी कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है। छएझ-२०२० के अंतर्गत बीई (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) के संशोधित पाठ्यक्रम में मैटेरियल साइंस कोर्स के संपादन में उन्होंने अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा, स्नातकोत्तर स्तर पर सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम निर्माण में भी उनका योगदान रहा है।

डॉ. क़ाज़ी तक़ीउद्दीन ज़हीरुद्दीन खडढए, खखखए और ख-ए के लाइफ मेंबर हैं। उन्होंने के. जे. सोमैया कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. विवेक सानपवार के मार्गदर्शन में पीएचडी का शोध कार्य पूर्ण किया। पीएचडी पूर्ण होने पर शिक्षण एवं अकादमिक जगत के साथ-साथ उनके परिजनों, मित्रों और विद्यार्थियों ने उन्हें हार्दिक बधाइयाँ दी हैं।

बीड के कृष्णा गायकवाड़ का अंडर-१४ महाराष्ट्र क्रिकेट टीम में चयन

बीड जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से बधाई

बीड (प्रतिनिधि) । १९ जनवरी

बीड जिला क्रिकेट एसोसिएशन के होनहार खिलाड़ी कृष्णा गायकवाड़ का १४ वर्ष से कम आयु वर्ग (अंडर-१४) की महाराष्ट्र क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर खेल जगत से उन्हें लगातार बधाइयाँ मिल रही हैं। कृष्णा गायकवाड़ ने निरंतर मेहनत, अनुशासित अभ्यास और उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर राज्य टीम में स्थान हासिल किया है।

कृष्णा गायकवाड़ की इस सफलता पर बीड जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर, डॉ. योगेश क्षीरसागर, सचिव आमेर सलीम सहित महेश वाघमारे, राजन सालवी, इरफान कुरैशी, मनोज जोगदंड, जावेद पाशा, रिज़वान खान, जैतुल्ला खान, सिद्दीक देशमुख, संजय उडान, शुभम धुत, शेख आरिफ, अतीक कुरैशी, सुनील गोपी शेट्टी, गोपाल गुरखूदे, सरफराज मोमीन, अक्षय नरवडे, पठान शाहरुख सहित अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों ने बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ व्यक्त कीं।

कृष्णा गायकवाड़ का यह चयन बीड जिले के लिए गर्व की बात है। खेल प्रेमियों ने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में वह राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करेंगे।

पान १ से

यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन...

अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर लगा रहे हैं।

रेमिटेंस: यूएई से भारतीय हर साल करीब २० बिलियन डॉलर भेजते हैं।

यूएई में भारतीयों की संख्या: सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय

यूएई में भारतीय सबसे बड़ा एक्सपैट्रिएट समुदाय हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार:

कुल संख्या: लगभग ४.३६ मिलियन (४३.६ लाख)।

यूएई की कुल आबादी में हिस्सेदारी: ३८-४०%।

पिछले दशक में दोगुनी वृद्धि: २०१४-१५ में करीब २२ लाख थे।

शहरवार वितरण: दुबई में सबसे ज्यादा (लगभग २२ लाख), अबू धाबी में ८-९ लाख, बाकी शारजाह आदि में।

राज्यवार: केरल से सबसे ज्यादा (लगभग ५०%), उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश/बिहार।

सांस्कृतिक और सुरक्षा जुड़ाव

यूएई में बना विशाल हिंदू मंदिर और ४३ लाख+ भारतीय मजबूत सांस्कृतिक सेतु हैं।

दोनों देश आतंकवाद विरोध और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ा रहे हैं।

शेख मोहम्मद बिन जायद का यह छोटा लेकिन प्रभावशाली दौरा भारत की बढ़ती वैश्विक साख का प्रमाण है। इतने व्यस्त और शक्तिशाली नेता (जिनके पास ८ निजी विमान और ७००+ कारों का काफिला है) का ढाई घंटे के लिए आना दोनों देशों की अनिवार्य साझेदारी को रेखांकित करता है। चाहे ट्रंप की शांति योजना हो या भविष्य के कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, भारत और यूएई अब वैश्विक एजेंडा तय करने में साथ खड़े हैं।

---

२९ महानगरपालिकाओं के...

सुबह ११ बजे कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें नगर विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित महानगरपालिकाओं के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे। शासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न की जाएगी।

बीएमसी का 'बॉस' पद किसके लिए?

मुंबई महानगरपालिका के महापौर पद पर कौन-सा वर्ग आरक्षित रहेगा, इस पर पूरे राज्य का ध्यान केंद्रित है। मुंबई का महापौर पद केवल प्रशासनिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए २२ जनवरी की यह आरक्षण लॉटरी राज्य की राजनीति के लिए एक अहम पड़ाव साबित होने वाली है।

समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज...

के निर्देश दिए गए। कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन की उपलब्धता की समीक्षा कर इन सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

इसके अलावा डेंटल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज शुरू करने के प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई। चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देकर भविष्य के लिए अधिक मानवबल तैयार करने पर बल दिया गया। सांसद बजरंग सोनवणे ने स्पष्ट कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे मराठवाड़ा के मरीजों को उनके क्षेत्र में ही आधुनिक, भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिलना चाहिए, इसके लिए सभी आवश्यक कदम तत्काल उठाए जाएं। स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और संस्थान के समग्र विकास के लिए अपना निरंतर प्रयास आगे भी जारी रहने की बात उन्होंने दोहराई।

राज्य के किसानों के...

को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय लागू करने की सलाह दी है।

राज्य सरकार का पत्र प्राप्त होने के बाद, एसएलबीसी ने सभी बैंकों को आरबीआई के दिशा-निर्देशों के तहत पात्र फसल कर्ज का पुनर्गठन करने और बाढ़ से प्रभावित किसानों से कर्ज वसूली स्थगित रखने के निर्देश दिए हैं।

अंबरनाथ नगर परिषद...

गुट के चार नगरसेवकों और एक अपक्ष को अपने पाले में लेकर ३२ सदस्यों की स्वतंत्र आघाड़ी बना ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस को उपनगराध्यक्ष पद देते हुए सत्ता स्थापित की गई और अन्य समितियों की नियुक्ति भी की गई। इसी के विरोध में भाजपा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अब अदालत ने रोक लगा दी है।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com